

वकिलांगता अधनियम के कर्यान्वयन में राज्यों की प्रगतिधीमी

चर्चा में क्यों?

दवियांग जन अधिकार अधनियम (RPWD) के कार्यान्वयन पर डसिबलिटी राइट इंडिया फाउंडेशन (DRIF) द्वारा 24 राज्यों में कयि गए एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि आधे से अधिक राज्यों ने पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद अभी तक राज्य के नयिमों को अधसूचति नहीं कयि है।

प्रमुख बदि

- सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि बिहार, चंडीगढ़, मणपुर, मेघालय, ओडशा, तेलंगाना, तमलिनाडु और पश्चिम बंगाल सहति दस राज्यों ने राज्य के नयिमों को अधसूचति कयि है।
- दवियांग जनों के रोजगार के संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय केंद्र (National Centre for Promotion of Employment for Disabled People- NCPEDP) और दवियांग जनों के अधिकारों पर राष्ट्रीय समिति (National Committee on the Rights of Persons with Disabilities- NCRPD) के सहयोग से आयोजति इस अध्ययन में कहा गया है कि दिसंबर 2016 में पारति इस अधनियम को सभी राज्यों द्वारा छह महीने के भीतर अधसूचति कयि जाना था।
- दवियांग जन अधिकार अधनियम के संबंध में राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी पर केंद्रति इस अध्ययन से पता चलता है कि 79.2% राज्यों ने RPWD अधनियम के कार्यान्वयन हेतु कोष का गठन नहीं कयि था।
- कोष का गठन करने वाले पाँच राज्यों में से तमलिनाडु द्वारा इस कोष के लयि 10 करोड़ रुपए आवंटति कयि गए, जबकि हिमाचल प्रदेश द्वारा 5 करोड़ रुपए आवंटति कयि गए।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि, "केवल तमलिनाडु द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में दवियांग जनों के लयि सहायता बढ़ाने के संबंध में कुछ कदम उठाए गए हैं।"
- अध्ययन में कहा गया है, "हालाँकि 62.5% राज्यों ने दवियांग जनों के लयि आयुक्त नयिकृत कयि हैं कति यह प्रगति पर्याप्त नहीं है। राज्य में आयुक्तों की सहायता के लयि केवल तीन राज्यों ने विशेषज्ञ सलाहकार समितियों का गठन कयि है।"
- इस अध्ययन के संबंध में प्रतिकरिया देने वाले 24 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश उच्चतम स्थान पर रहा, इसके बाद ओडशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश का स्थान रहा।
- जम्मू-कश्मीर के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अध्ययन में सबसे नचिले स्थान पर थे, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दल्लि 12वें स्थान पर थी।
- अध्ययन में कहा गया है कि 58.3% राज्यों ने अधनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लयि जलिलों में वशिष न्यायालयों को अधसूचति नहीं कयि है, जबकि 87.5% राज्यों ने कानूनी तौर पर अनविर्य एक वशिष सरकारी अभयोजन को नयिकृत नहीं कयि है।

अध्ययन से संबंधति आँकड़े

- अध्ययन में प्रतिकरिया देने वाले राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों की संख्या 24 (66.7%) थी। केवल 41.7% राज्यों ने ही राज्य नयिमों एवं वशिष न्यायालय को अधसूचति कयि था।
- अध्ययन के अनुसार, 50% राज्य और केंद्रशासति प्रदेश ऐसे थे जिन्होंने राज्य सलाहकारी बोर्ड का गठन नहीं कयि था। देश में 79.2% राज्य ऐसे थे जहाँ राज्य कोष का आवंटन नहीं कयि गया था।
- 37.5% राज्य और केंद्रशासति प्रदेश ऐसे थे जहाँ दवियांग जनों के लयि राज्य आयुक्तों की नयिकृति नहीं की गई थी। 12.5% राज्यों में ही वशिष सरकारी अभयोजन की नयिकृति की गई थी।

स्रोत : द हदि